अभ्यावेदन भेजा गया था। दिनांक 31.1.1996 के इस अभ्यावेदन में शिक्षकों की सेवा-शर्तों में कुछ सुधार करने के लिए कहा गया था। उनकी मांग बिना पी०एच०डी० डिग्री किये लेक्चरर से रीडरशिप और रीडर से प्रोफेसरशिप पर पदोन्नति देने के संबंध में थी। सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से इन मांगों की जांच कर ली है और इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतन पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है।

शिक्षकों की भर्ती के संबंध में समाचार

*398. **श्री शिव चरण सिंह:**
श्री राघवजी:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1997 के** "जनसत्ता" में "शिक्षकों की नियुक्ति की संदेहास्पद प्रक्रिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

Development of moral standard of school students

*399. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the measures being contemplated by Government to improve the present standard of school education in order to develop the moral standrad of students from the grassroot level;

(b) whether Government are aware of the changes that have occurred in the overall thinking of younger generation for casteism and separation that may endanger the national integration; and

(c) if so, the measures contemplated to meet such challenges in the interest of the country's integrity?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) to (c) The National Policy on Education 1986 and the Programme of Action 1992 have dealt with the question of development of moral standards by way of enrichment of the existing curriculum by incorporating culture content at two levels. At one level, India's common cultural heritage has been identified as one of the elements of core curriculum. At another level, a synthesis has been envisaged between changed oriented technologies and cultural traditions through educational institutions. The NCERT has also prepared exemplary instructional package for the benefit of school students. The cultivation of social and moral value is dealt both at the elementary as well as secondary educaiton. The Central Board of Secondary Education has directed its affiliated schools for inculcation of universal and human values both in general and in relation to the school curicula. Imparting of value education is regarded as an integral part of the entire educational process as distinct from dissemination of values through special lectures on morality or through textbooks.

The textbooks published by the NCERT include elements of universal values, which are interwoven in the curriculum of various subejcts. Further, the Teacher Education curricula both at the Elementary and Secondary level incorporate value education components. Some of the schools play a vital role in bringing out national integration and social cohesion among the young minds. The programme design in the schools also awaken in the students an awareness of national integrity and for this purpose, various steps have been taken, such as, community living based on cooperative self-help and democratic principles and also the study of India's history and

culture in the curriculum at various stages of education. The school programmes are also suplemented by other activities such as programmes for bringing students together on a common platform and enable them to gain first hand knowledge of the diversified culture of the country through eduational tours, development of modern and Indian classical languages and making rich store house of lactures available to a large number of schools in different parts of the country.,

The Central Institute of Educational Technology (CIET), a constituent unit of the NCERT has produced a wide range of educational technology material—films, video programmes, charts, slides, film strips pertaining to different areas of learning in the general curriculum including value education. The NCERT has also produced recorded cassettes of 15 community songs in different Indian languages to instil in children the spirit of unity and love for the country. Teachers are trained in specially organised camps in teaching, to sing these songs as part of their curricular programmes. The songs are chosen for their message of universal love, unity and patriotism.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध निर्णय

*400. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों में वायु और जल प्रदूषण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 प्रतिशत से भी अधिक मुकदमों का निर्णय बोर्ड के खिलाफ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्थिति की समीक्षा कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर किए गए 6565 मामलों में से 1313 मामलों में निर्णय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विरुद्ध गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

सूखाग्रस्त गांव घोषित करने के संबंध में मानदण्ड

2874. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यूनतम तथा अधिकतम वर्षा के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यह योजना कब से चालू है और इस योजना के प्रारम्भ के समय गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाया गया था तथा इस समय किस मानदण्ड का अनुपालन किया जा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) गांवों को सूखा प्रभावित घोषित करना राज्य सरकारों का विषय है। इस प्रकार की घोषणा करने का मानदण्ड एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। राज्य सरकारें राज्य राहत मैन्युअलों अथवा इस विषय पर अन्य सरकारी आदेशों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे पर विचार करते समय राज्य सरकारें अपर्याप्त अथवा भारी वर्षा के कारण फसल को हुई क्षति को ध्यान में रखती है। सामान्यतया, वे गांव जहां सामान्य की तुलना में 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल की हानि होती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित माने जाते हैं। गांवों/ब्लाकों/तहसीलों को सूखे से प्रभावित घोषित करते समय निम्नलिखित घटकों की भी ध्यान में रखा जाता है।

(1) खाद्यान्नों तथा चारे की उपलब्धता और मूल्य।

(2) रोजगार की स्थिति और मजदूरी का रुख।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिक वर्ग का असामान्य स्थान परिवर्तन।

(4) विपत्ति के संकेत देने वाले अन्य घटक।

यह प्रणाली विभिन्न राज्यों में विभिन्न समय से लागू है।